## न्यूज डायरी

### भारतीय बहुओं को निवास परमिट देने की तैयारी में नेपाल सरकार

**एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)** काठमांडू। भारत समेत सभी विदेशी बहुओं को 7 साल बाद नागरिकता देने के फैसले को लेकर हो रही आलोचनाओं से बेपरवाह नेपाल सरकार अब ऐसी लड़कियों को निवास परमिट देने की तैयारी कर रही है। नेपाल की संसदीय राज्य मामले और सुशासन कमिटी ने प्रस्ताव दिया है कि नेपाली युवकों से शादी करने वाली विदेशी बहुओं को नागरिकता मिलने तक निवास परमिट दिया जाए। नेपाल में निवास परमिट का प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने नागरिकता को लेकर एक विवादित प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव के तहत विदेशी बहुओं को नेपाली युवक से शादी के 7 साल बाद नेपाल की नागरिकता दी जाएगी। भारत और नेपाल के बीच रोटी–बेटी का साथ रहा है। माना जा रहा है कि ओली सरकार के इस प्रस्ताव के निशाने पर भारतीय बेटियां हैं जो बहू बनकर नेपाल जाती हैं।

### मिनियापोलिस में गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत,11लोग घायल

**एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)** मिनियापोलिस। मिनियापोलिस के बाजार क्षेत्र में गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। गोलीबारी की यह घटना शहर के 'अपटाउन' इलाके में आधी रात के बाद हुई । यह एक बाजार क्षेत्र है, जहां नाइटलाइफ हब और एप्पल तथा नामी गिरामी कंपनी के स्टोर हैं। पुलिस ने पहले कहा था कि 10 लोगों को गोली मारी गई है और वे गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन उन्होंने सुबह तीन बजे के बाद ट्वीट कर जानकारी दी कि एक आदमी की अस्पताल में मौत हो गई है और घायल हुए अन्य लोगों की जान को कोई खतरा नहीं है। पुलिस ने कहा कि उनका मानना है कि एक से अधिक लोग गोलीबारी कर रहे थे। मिनियापोलिस के पुलिस प्रमुख मेडारिया अर्रादोंडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा यह ''दुखद और बेतुकी हिंसा'' है और उन्होंने हिंसा की बढ़ती घटनाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बताया। उन्होंने कहा, ''हमारे पास संदिग्धों के संबंध में यकीनन कई सुराग हैं और हम एफबीआई और एजेंसियों से सहायता ले रहे हैं।''

### पाकिस्तान ने संघर्षविराम उल्लंघ को लेकर भारत के उपउच्चायुक्त को तलब किया

**एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)** इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कथित रूप से संघर्षविराम उल्लंघन किये जाने पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए रविवार को भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि महानिदेशक (दक्षिण एशिया एवं दक्षेस) हाफिज चौधरी ने 20 जून को हाजीपीर और बेदौरी सेक्टरों में भारतीय सुरक्षाबलों द्वारा ''कथित रूप से किये गये संघर्षविराम उल्लंघन पर कड़ा विरोध दर्ज'' कराया। पाकिस्तान ने दावा किया कि बिना किसी उकसावे के की गयी अंधाधुंध गोलीबारी में दो व्यक्तियों की जान चली गयी, जबकि एक घायल हो गया। बयान के अनुसार चौधरी ने कहा कि भारत सरकार को जरूर अहसास करना चाहिए कि उसकी गैर जिम्मेदाराना नीतियों और एकतरफा कार्रवाई इस क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा को खतरे में डाल रही है, भारत को क्षेत्रीय शांति एवं समृद्धि के हित में जिम्मेदारी से काम करना चाहिए।

### इमरान के मंत्री ने कोविड–19 की अलग परिभाषा, ट्विटर पर हुई ट्रोल

**एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)** इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस को लेकर कितनी जागरूकता है इसकी मिसाल इमरान खान के एक मंत्री ने दी। एक टीवी चौनल से बातचीत के दौरान पाकिस्तानी जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री जरताज गुल ने कोविड– 19 का मतलब अपने हिसाब से ही बयां कर दिया। जिसके बाद कोरोना की नई परिभाषा का यह विडियो सोशल मीडिया में देखते ही देखते वायरल हो गया। दरअसल एक टीवी चर्चा के दौरान इमरान की मंत्री जरताज गुल ने कहा कि कोविड–19 का मतलब है कि इसके 19 प्वाइंट्स हैं जो किसी भी मुल्क में किसी भई तरीके से अप्लाइ हो सकता है और अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करें।

# भारतीयों ने चलाई गोली तो अंजाम बुरा: चीन

**धमकी**

■1962 के युद्ध की याद दिलाते हुए धमकी भी दी

भारतीय सैनिकों को हथियार के इस्तेमाल की छूट मिलने से चीन का सरकारी अखबार भड़का

**एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)**

पेइचिंग। लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारतीय सैनिकों को नियंत्रण रेखा पर असाधारण परिस्थितियों में हथियार के इस्तेमाल की छूट मिलने से चीन का सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा है। चीनी अखबार ने धमकी दी कि अगर भारतीय सैनिकों ने गोली चलाने की हिमाकत की तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। चीनी अखबार ने अपने संपादकीय में वर्ष 1962 के युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि आज चीन की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों ही भारत से ज्यादा मजबूत है।

ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अगर गोली चलाने का आदेश सच साबित हुआ तो ताजा घटनाक्रम भारतीय–चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच हुए विश्ध्वास बहाली के समझौते का गंभीर उल्लंघन होगा। सीमा पर झड़प कभी–कभी होती है और दोनों ही देशों ने कई दशकों से गोली नहीं चलाई है। अगर भारतीय सैनिकों ने भविष्य में चीनी सैनिकों के खिलाफ हथियारों का इस्ध्तेमाल किया तो सीमाई इलाकों में तस्ध्वीर इससे उलट होगी।

**वर्ष 1962 की तुलना में आज स्थिति अलग नहीं:** चीनी अखबार ने कहा, मैं भारत के राष्ट्रवादियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आपके सैनिक बिना हथियारों के युद्ध में जीत नहीं सकते हैं तो हथियार उनकी मदद नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि चीन की सैन्ध्य ताकत भारत से ज्यादा आधुनिक और मजबूत है। हम यह बताना चाहेंगे कि 1962 से आज की स्थिति ज्यादा अलग नहीं है। चीन की जीडीपी भारत की पांच गुना और चीन का सैन्य खर्च भारत का तीन गुना ज्यादा है।

ग्लोबल टाइम्ब्स ने कहा, अगर भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद को मुठभेड़ या स्थानीय युद्ध में बदला तो यह अंडे के पहाड़ से टकराने जैसा होगा। उसने कहा कि चीन भारत के साथ तनाव को भड़काना नहीं चाहता है लेकिन हमारे अंदर भारतीयों की किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब देने की क्षमता है। यह भारत के हित में है कि वह सीमा विवाद को नियंत्रण में रखे।

**भारत सरकार ने सेना को दी पूरी आजादी:** इससे पहले पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सैनिकों को श्पूरी आजादी दे दी है। सरकार ने एलएसी पर नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत सेना के फील्ड कमांडरों को यह अधिकार दिया गया है कि वह विशेष परिस्थितियों में जवानों को हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं।

सरकार के नए नियमों के अनुसार, एलएसी पर तैनात कमांडर सैनिकों को सामरिक स्तर पर स्थितियों को संभालने और दुश्मनों के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी छूट होगी।

## चीन ने लद्दाख से अरुणाचल तक तैनात किए विमान

**एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)**

पेइचिंग। लेह में भारत के मिग–29 और अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्टर तैनात करने के बाद चीन ने भी लद्दाख से सटे अपने दो एयरबेस होटान, नग्यारी, शिगात्से (सिक्किम के पास) और नयिंगची (अरुणाचल प्रदेश के पास) में बड़े पैमाने पर फाइटर जेट, बमवर्षक विमान और हेलिकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। यही नहीं चीन की सेना ने पेंगांग सो झील पर फिंगर 4 के आगे भारतीय सैनिकों को गश्ध्त से रोकने के लिए अपनी आक्रामक कार्रवाई और नघ्गिरानी को बढ़ा दिया है।

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत से लगी अपनी पूरी सीमा पर स्थित हवाई ठिकानों होटान, नग्यारी, शिगात्से और नयिंगची में अतिरिक्त फाइटर जेट, बॉम्बर और लड़ाकू हेलिकॉप्टरों को तैनात किया है। पीएलए अरुणाचल की सीमा पर भी अपनी गतिविधि को तेज कर दिया है। पेंगांग सो झील पर जहां चीन की सेना एलएसी को बदलना चाहती है, वहीं चीनी सेना ने गोगरा हॉट स्प्रिंग में भी बड़े पैमाने पर सैनिकों और हथियार तैनात किए हैं।

चीन की ताजा हरकत से भारत के देपसांग, मुर्गो, गलवान, हॉट स्प्रिंग, कोयूल, फूकचे और देमचोक को खतरा का काफी बढ़ गया है। भारत ने भी चीन की इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी तैयारी काफी बढ़ा दी है।

**हॉन्ग–कॉन्ग पर अधिकार बढ़ाने का चीन का प्लान**

**एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)** हॉन्ग–कॉन्ग। चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए हॉन्ग–कॉन्ग में एक विशेष ब्यूरो स्थापित करने की योजना बनाई है। सरकारी मीडिया में शनिवार को जारी खबरों में हॉन्ग–कॉन्ग में लागू किए जा रहे विवादित नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में कुछ जानकारी सामने आई है, जिसमें यह बात पता चली है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार हॉन्ग–कॉन्ग में वित्त से लेकर आव्रजन तक सभी सरकारी विभागों के निकाय सीधे पेइचिंग की केन्द्र सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे। चीन की विधायिका ने गुरुवार को हॉन्ग–कॉन्ग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बिल का मसौदा पारित किया था। इस कानून को लेकर चीन पर अर्ध–स्वायत्त हॉन्ग–कॉन्ग के कानूनी और राजनीतिक संस्थानों को कमजोर करने के आरोप लगे हैं।

## नेपाल के गांव पर तीन साल से चीन का कब्जा, ओली सरकार ने साधी चुप्पी

**एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)**

काठमांडू। भारत के साथ कालापानी सीमा विवाद का मुद्दा उठाने वाले नेपाल के रुई गांव पर पिछले तीन साल से चीन ने कब्ज्जा कर रखा है। पिछले कुछ समय से एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठा रही नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने ड्रैगन की इस नापाक हरकत पर चुप्पी साध रखी है। भारत के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करने वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर मौनव्रत धारण कर लिया है।

करीब 60 साल तक नेपाल सरकार के अधीन रहने वाले रुई गांव के गोरखा अब चीन के दमनकारी शासन के अधीन हो

### कम्ध्युनिस्ट पार्टी ने इस पर मौनव्रत धारण किया

गए हैं। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट्ट के मुताबिक रुई गांव वर्ष 2017 से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा हो गया है। इस गांव में अभी 72 घर हैं। रुई गांव अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण हो गया है। रुई गांव के सीमा स्तंभों को अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए हटा दिया गया है।

**बह्दर के पिलर को लगाते समय लापरवाही:** नेपाल के भू–राजस्व कार्यालय गोरखा के अनुसार, उनके पास अभी भी रुई गांव के निवासियों से एकत्र राजस्व का रेकॉर्ड है। रुई गांव के निवासियों की ओर से दिए गए राजस्ध्व का विवरण भूमि राजस्व कार्यालय में सुरक्षित है। कार्यालय के एक सहायक कर्मचारी ने कहा, कार्यालय के रेकॉर्ड अनुभाग में अथारा साया खोले से रुई तक के लोगों के राजस्व का रेकॉर्ड हैं।

नेपाली इतिहासकार रमेश धुंगल का कहना है कि वर्ष 2017 तक रुई और तेइगा गांव देश के गोरखा जिले के उत्तरी भाग में थे। उन्ह्होंने कहा, रुई गांव नेपाल का हिस्सा है। न तो हमने इसे युद्ध में खोया और न ही यह तिब्बत से संबंधित किसी विशेष समझौते या अनुबंध के अधीन था। नेपाल ने बॉर्डर के पिलर को लगाते समय लापरवाही की जिसके कारण हमने रुई और तेघा दोनों गांव खो दिए।

### भारत–चीन तनाव के बीच नेपाल में मांग, ड्यूटी पर न लौटें गोरखा सैनिक

**एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)** काठमांडू। भारत के पड़ोसी देश में चीन के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है। पहले देश की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बैठक की। अब देश में मांग उठ रही है कि नेपाली गोरखा नागरिक भारतीय सेना में शामिल न हों। नेपाल की एक प्रतिबंधित पार्टी ने मांग की है कि गोरखा नागरिक भारत की ओर से चीन के लिए लड़ाई न लड़ें। प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेत्र बिक्रम चंद ने काठमांडू में नेतृत्व से यह अपील की है कि गोरखा नागरिकों को भारतीय सेना का हिस्सा बनने से रोका जाए। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है, गलवान घाटी में भारतीय जवानों के मारे जाने के बाद भारत और चीन में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने गोरखा रेजिमेंट के नेपाली नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी छुट्टियां रद्द करके ड्यूटी पर वापस आएं। इसका मतलब है कि भारत हमारे नेपाली नागरिकों को चीन के खिलाफ सेना में उतारना चाहता है। बयान में कहा गया है कि गोरखा सैनिकों को भारत द्वारा तैनात किया जाना नेपाल की विदेश नीति के खिलाफ जाएगा।